

DAILY **CURRENT AFFAIRS**

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 24-09-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 24 Sep, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus :GS 2& 3 : International Relations& Environment / Prelims	COP30 के लिए ऊर्जा दक्षता लक्ष्य बढ़ा सकता है भारत
Page 04 Syllabus :GS 3 : Disaster Management / Prelims	आपदा संभावित क्षेत्रों में राजमार्ग ढहने से रोकने के लिए केंद्र नए नियम जारी करेगा
Page 06 Syllabus :GS 1 : Social Issues/ Prelims	राष्ट्रपति ने महिला केंद्रित फिल्मों की सराहना की
Page 07 Syllabus :GS 3 : Science and Tech / Prelims	आईपीआर गांधीनगर ने भारत की फ्यूजन पावर योजनाओं के लिए रोडमैप का प्रस्ताव रखा
Page 10 Syllabus :GS 2 : International Relations / Prelims	भारत-चीन सीमा का मानचित्रण
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus :GS 2 : International Relations	राज्य का अधिकार: फिलिस्तीन की मान्यता केवल प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है

भारत ब्राजील के बेलेम (नवंबर 2025) में COP30 में अपना अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। एनडीसी पेरिस समझौते (2015) के तहत देश-विशिष्ट जलवायु कार्रवाई लक्ष्य हैं, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस (अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस) से नीचे सीमित करना है। भारत द्वारा अपने ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को बढ़ाने की संभावना है, जो आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को संतुलित करते हुए सतत विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

India may increase energy efficiency target for COP30

Jacob Koshy
NEW DELHI

India will submit its updated Nationally Determined Contributions (NDCs) around the commencement of the UN Climate Change Conference COP30 in Brazil on November 10, likely with an increased target for energy efficiency improvement, sources in the Environment Ministry indicated to *The Hindu*.

The NDCs are renewable-energy adoption goals set by a country as part of being a signatory to the Paris Agreement - under which countries must regulate their fossil fuel consumption to keep the globe from heating 2 degrees Celsius, and as far as possible, 1.5 degrees Celsius above that in pre-industrial times.

As part of this, countries are required to update their NDCs every five years. India last updated its

NDCs in 2022, when it committed to reduce the emissions intensity of its GDP by 45% of 2005 levels; source half of its electric power capacity from non-fossil fuel sources; and create a carbon sink of at least two billion tonnes by 2030.

Emissions intensity of the GDP refers to the amount of carbon emitted per unit of GDP and does not mean a reduction in net emissions. As of December 2023, India reported to the United Nations climate-governing body that the emissions intensity of its GDP had been reduced by 33% between 2005 and 2019. This June, India reported installing at least 50% of its power capacity from non-fossil fuel sources.

Planet getting warmer

The NDCs are of particular significance this year because Brazil, which as-



Clean energy: India has committed to source half of its electric power capacity from non-fossil fuel sources by 2030. REUTERS

sumes the COP presidency in Belém, has stressed that a major effort this year will be to assess what hindered countries from achieving their stated NDCs.

All commitments by countries, even if achieved perfectly, cannot stop the globe from heating to an average of 3 degrees Celsius by the century - well short of the Paris Agreement goals.

Overall, the ambition to

undertake significant emission cuts seems muted.

EU climate target looms

The European Union has yet to announce a 2035 target, though it has a long-term goal to be "net zero" by 2050.

The EU commission this July had proposed an amendment to the EU climate law enabling a 90% cut in emissions compared to 1990 by 2040.

Though they were to vote on a target for 2035 last week, France and Germany weighed in to postpone a vote on the matter.

The EU is expected to submit its NDCs ahead of COP30 with an indicative 2035 target in a range from 66.25% to 72.5%, compared with the 1990 levels. Australia this month updated its NDCs to say that it "aimed" to cut emissions to 62%-70% of 2005 levels by 2035.

The United States has exited the Paris Agreement and it remains to be seen if China will announce ambitious NDCs ahead of COP30.

Major reductions, sources in the Environment Ministry suggest, would likely result from bilateral agreements between countries where developed and developing countries jointly invested in clean energy projects and shared the resulting cut in emissions, as

computed by an approved methodology, as carbon credits.

Indian initiatives

India has recently signed such an agreement called a JCM (Joint Crediting Mechanism) with Japan and is in talks with other countries. However it will be a few years before such projects practically kick in.

"Developed countries are not willing to part with the necessary finance to make good on ambitious goals and developing countries require fossil fuels for their development," an Environment Ministry official added.

India is also expected to operationalise the India Carbon Market by 2026 - under which 13 major sectors will be given mandatory emission-intensity targets - and can trade their resulting savings, if any, via emission reduction certificates.

स्थैतिक संदर्भ

1. पेरिस समझौता और NDC

- COP21 (2015) में अपनाई गई कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतराष्ट्रीय संधि।
- देशों को हर 5 साल में एनडीसी जमा करने और अपडेट करने की आवश्यकता होती है।
- शमन (उत्सर्जन में कटौती), अनुकूलन और जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित करें।

2. भारत के वर्तमान NDC (2022 में अद्यतन):

- 45 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030% तक कम करना।
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
- वनीकरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाएं।

3. कॉन्सेप्ट चेक (प्रीलिम्स):

- उत्सर्जन तीव्रता = सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई CO₂ उत्सर्जन (पूर्ण उत्सर्जन कटौती नहीं)।
- कार्बन सिंक = वनों, मिट्टी, महासागरों द्वारा कार्बन का अवशोषण।
- कार्बन क्रेडिट = उत्सर्जन में कमी के लिए व्यापार योग्य प्रमाण पत्र।

वर्तमान संदर्भ

- **भारत की प्रगति:**
 - उत्सर्जन की तीव्रता में 33% की कमी (2005-2019)।
 - गैर-जीवाश्म ईंधन से स्थापित >50% बिजली क्षमता (जून 2024)।
- **NDC में अपेक्षित संवर्द्धन (2025):**
 - ऊर्जा दक्षता पर ध्यान बढ़ाया गया।
 - भारत कार्बन बाजार का विस्तार (2026): अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्यों के साथ 13 क्षेत्र, उत्सर्जन में कमी प्रमाण पत्र के माध्यम से व्यापार योग्य।
 - जापान के साथ संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग; इसी प्रकार के समझौतों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
- **वैश्विक परिदृश्य:**
 - यूरोपीय संघ: 2040 तक 90% उत्सर्जन कटौती (1990 बेसलाइन) का प्रस्ताव; 2035 के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
 - ऑस्ट्रेलिया: 2035 तक उत्सर्जन में 62-70% (2005 बेसलाइन) में कटौती करने का अद्यतन लक्ष्य।
 - अमेरिका: ट्रम्प के तहत पेरिस समझौते से बाहर हो गया, भविष्य का रुख अनिश्चित
 - चीन: महत्वाकांक्षी एनडीसी पर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है।
- **चुनौतियों:**
 - वित्त अंतर: विकसित राष्ट्र सालाना 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हैं।
 - विकास बनाम डीकार्बोनाइजेशन: विकासशील देश (भारत सहित) अभी भी विकास के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं।

निष्कर्ष

COP30 में अपने ऊर्जा दक्षता लक्ष्य को बढ़ाने का भारत का निर्णय विकासात्मक हितों की रक्षा करते हुए जलवायु नेतृत्व के प्रति उसके सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालाँकि, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करना वैश्विक जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रभावी कार्बन बाजारों पर निर्भर करता है। दुनिया को पेरिस समझौते की तापमान सीमा के भीतर रहने के लिए, विकसित और विकासशील दोनों देशों को महत्वाकांक्षा बढ़ानी चाहिए और निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र के माध्यम से सहयोग करना चाहिए।

भारत का मार्ग बड़ी वैश्विक दुविधा को दर्शाता है: जलवायु संकट का तत्काल समाधान करते हुए विकास और गरीबी में कमी सुनिश्चित करना।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: पेरिस समझौते (2015) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना सभी पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
2. इसके तहत, देशों को हर पांच साल में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) जमा करने और अपडेट करने की आवश्यकता होती है।
3. इसका प्राथमिक लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं विकास की अनिवार्यता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन को उजागर करती हैं। COP30 में भारत के संभावित बड़े हुए ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के आलोक में चर्चा करें। **(250 शब्द)**

केंद्र सरकार पहाड़ी और आपदा-प्रवण क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण से पहले ढलान स्थिरीकरण को अनिवार्य करने के लिए नए दिशानिर्देश पेश करने की योजना बना रही है। यह कदम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़क ढहने की बार-बार घटनाओं के बाद आया है, जहां बादल फटने और बाढ़ ने कीरतपुर-मनाली राजमार्ग (एनएच -21) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ राजमार्गों को मजबूत करना आपदा लचीलापन, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

Centre to issue new norms to curb highway collapse in disaster-prone areas

Jagriti Chandra
NEW DELHI

The Union government is “cognisant” of concerns after sections of highways were washed away following cloudbursts and floods in parts of Himachal Pradesh and Uttarakhand, and will frame new guidelines to focus on “slope stabilisation” to curb road collapse during natural disasters, a senior official of the Road Transport and Highways Ministry said.

“We will be issuing new guidelines mandating slope stabilisation prior to road construction, rather than as a post-construction measure, in hilly regions. Additionally, we will revise concessionaire agreements to incorporate these requirements for all future projects,” V. Umashankar, Secretary, Road Transport and Highways Ministry, told *The Hindu*.

The official said that following the recent incidents of road collapses, includ-



Damage to National Highways was mostly observed in sections constructed along riverbanks, says Transport Ministry official. PTI

ing the 15 damaged sites along National Highway-21 (Kiratpur-Manali Highway), it was observed that the locations which underwent slope stabilisation measures withstood the impact of cloudbursts and floods. Slope stabilisation is an engineering process of strengthening an unstable slope to prevent landslides and erosion. It involves techniques that increase a slope's safety by controlling soil or rock movement, managing water drainage, and reinforcing the ground. Common

methods include building retaining walls, soil nails, anchors, shotcrete, drainage systems, vegetation planting, and adjusting slope shape to improve stability.

The official said damage to National Highways was mostly observed in sections constructed along riverbanks, exacerbated by rising river levels. The damage was observed on the “valley side”, or the side of the road that slopes down towards the river flowing through the valley below, he added.

स्थैतिक संदर्भ

1. राष्ट्रीय राजमार्गों का महत्व:

- भारत के सड़क नेटवर्क का केवल ~2% होने के बावजूद ~40% सड़क यातायात को ले जाएं।
- आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, आपदा राहत और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है।

2. पहाड़ी इलाकों में चुनौतियाँ:

- नाजुक भूविज्ञान, भूकंपीय गतिविधि, और तीव्र वर्षा की घटनाएं (बादल फटना, प्लैश बाढ़)।
- अस्थिर ढलान, भूस्खलन, कटाव और नदी के किनारे काटना।
- जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के कारण जोखिम बढ़ जाता है।

3. ढलान स्थिरीकरण तकनीक (प्रारंभिक प्रासंगिकता):

- दीवारों को बनाए रखना, मिट्टी की कील, लंगर, शॉटक्रीट।
- वनस्पति रोपण (बायो-इंजीनियरिंग)।
- भूतल जल निकासी और उपसतह जल प्रबंधन।
- ढलान का पुनःस्तरीकरण और सीढ़ीनुमा निर्माण।

वर्तमान संदर्भ

• मुख्य निर्णय:

- सड़क निर्माण से पहले ढलान स्थिरीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, न कि क्षति होने के बाद।
- पहाड़ी क्षेत्रों में भविष्य की सभी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए रियायतग्राही करारों को संशोधित करना।

• टिप्पणियों:

- ढलान स्थिरीकरण वाले स्थान बाढ़ और बादल फटने से बच गए, जबकि असुरक्षित खंड ढह गए।
- नदी के बढ़ते स्तर के कारण नदी के किनारे घाटी के हिस्सों में सबसे गंभीर नुकसान।

• प्रभाव:

- सड़क ढहने, आर्थिक नुकसान और यात्रा व्यवधानों में अपेक्षित कमी।
- हिमालयी राज्यों में पर्यटकों, स्थानीय लोगों और माल ढुलाई के लिए सुरक्षा बढ़ाता है।
- अन्य जलवायु-संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।

मुद्दे और चुनौतियां

- ढलान स्थिरीकरण की उच्च लागत परियोजना व्यय को बढ़ा सकती है।
- नाजुक हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में भूमि अधिग्रहण और पारिस्थितिक चिंताएं।
- निरंतर निगरानी और रखरखाव की आवश्यकता।
- पूर्व चेतावनी और तैयारी के लिए आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ समन्वय।

निष्कर्ष

राजमार्ग परियोजनाओं में ढलान स्थिरीकरण को अनिवार्य करने का कदम जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा योजना की ओर बदलाव को दर्शाता है। हालांकि यह प्रारंभिक लागत बढ़ा सकता है, सुरक्षा, कम आर्थिक नुकसान और आपदा की तैयारी के मामले में दीर्घकालिक लाभ खर्चों से अधिक है। भारत के लिए, जहां सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संवेदनशीलता के साथ इंजीनियरिंग समाधानों को एकीकृत करना आवश्यक है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: सड़क निर्माण में ढलान स्थिरीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक निर्माण के बाद की गतिविधि है जो सड़क क्षति होने के बाद ही शुरू की जाती है।
2. इसमें मिट्टी या चट्टान की गति, जल निकासी और जमीन के सुदृढीकरण को नियंत्रित करना शामिल है।
3. हिमालयी राज्यों में नदी के किनारों पर बने राजमार्ग खंडों में ढलान स्थिरीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के हिमालयी राज्यों में राजमार्ग निर्माण की चुनौतियों की गंभीर जांच करें। जलवायु-लचीला सड़क बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग और नीतिगत उपायों का सुझाव देना। (150 शब्द)

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह (2023) ने महिला-केंद्रित कथाओं, सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रीय मूल्यों को चित्रित करने में भारतीय सिनेमा की उभरती भूमिका पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करते हुए सामाजिक जागरूकता के माध्यम के रूप में सिनेमा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने जूरी पैनल में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया और पितृसत्ता, लैंगिक समानता और युवा संवेदनशीलता के मुद्दों को संबोधित करने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित किया।

President lauds women-centric films

At National Film Awards ceremony, Murmu notes recognition of films focusing on women; she calls for adequate representation of women on the jury panels, says films should spread social awareness; receiving Dadasaheb Phalke Award, actor Mohanlal says cinema is the 'heartbeat of his soul'

The Hindu Bureau
NEW DELHI

President Droupadi Murmu on Tuesday presented the prestigious Dadasaheb Phalke Award for 2023 to actor Mohanlal and gave away awards to the other winners at the 71st National Film Awards ceremony. "Cinema is the heartbeat of my soul. Jai Hind," Mohanlal said after receiving the country's highest cinema honour.

Congratulating all the winners, Ms. Murmu spoke about Mohanlal's phenomenal contributions, stating that the accomplished actor effortlessly portrayed emotions ranging from the most gentle to the most intense.

She noted that good films focusing on women were being made and recognised. "We all see that women, at some level, struggle with patriarchy and prejudiced attitudes. Today, the award-winning films include stories of mothers shaping the moral character of their children, women uniting to challenge social norms..., the stories of courageous women who raise their voices against patriarchal structures," she said, praising such filmmakers.



Top performances: The President gives the Dada Saheb Phalke Award to Mohanlal, the best male actor award to Shah Rukh Khan for *Jawan* and Vikrant Massey for *12th Fail*; and best female actor award to Rani Mukerjee for *Mrs. Chatterjee vs Norway*. SUSHIL KUMAR VERMA

The President said there should be adequate representation of women on the central and regional panels of the jury.

Underscoring the importance of cinema in spreading awareness of, and sensitivity to, social issues, particularly among the youth, Ms. Murmu said cinema should not only be popular but also serve a larger public interest. The President commended everyone involved in the award ceremony for en-

couraging films that focus on children, especially girls. Six child actors won awards this year.

Notable awards

The best male actor award went to Shah Rukh Khan for *Jawan* and Vikrant Massey for *12th Fail*, which was also declared the best feature film. Rani Mukerji got the best female actor award for her role in *Mrs. Chatterjee vs Norway*. The best direction award was bagged by Sudipto Sen for

The Kerala Story (Hindi), which also won in the best cinematography (Prasanna Mohapatra) category. P.V.N.S. Rohit and Shilpa Rao were adjudged the best male and female singers for the song *Premisthuna* in *Baby* (Telugu), which also won for the best screenplay (Sai Rajesh Nee- lam) along with *Parking* (Tamil) and *Chaleya* in *Jawan* (Hindi). The best debut film award went to Ashish Bende for *Aatma-pamphlet* (Marathi), and

the best popular film providing wholesome entertainment to Karan Johar-directorial *Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani*. Meghna Gulzar's *Sam Bahadur* was the best feature film promoting national, social, and environmental values.

Sudhakar Reddy Yakanti-directed *Naal 2* (Marathi) was adjudged the best children's film and *Hanu-Man* (Telugu) the best film in the animation, visual effects, gaming and comic category.

The best male actor in a supporting role award was shared by Vijayaraghavan for *Pookkaalam* (Malayalam) and Muthupettai Somu Bhaskar for *Parking* (Tamil). Urvashi won the award for the best female actor in a supporting role for *Ullozhukku* (Malayalam) along with Janki Bodiwala for *Vash* (Gujarati).

The best child artiste award went to Sukriti Veni Bandreddi for *Gandhi Tatha Chettu* (Telugu), Kabir Khandare for *Gypsy* (Marathi), and Treasha Thosar, Shrinivas Pokale and Bhargav Jagtap for *Naal 2*.

The awards for music direction went to G.V. Prakash Kumar in *Vaathi* (Tamil) and Harshavardhan Rameshwar in *Animal* (Hindi); and for lyrics to Karsarla Shyam for the song *Ooru Palleturu* in *Balagam* (Telugu).

Deepak Kingrani won the award for the best dialogue writer for the Hindi film *Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai*. Rongatapu 1982 (Assamese), *Deep Fridge* (Bengali), *Parking* (Tamil), *Kandeelu* (Kannada), *Shamchi Aai* (Marathi), *Puskara* (Odia), *Godday Godday Chaa* (Punjabi), and *Bhagavanth Kesari* (Telugu) won in the language film categories.

स्थैतिक संदर्भ

1. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार:

- 1954 में स्थापित, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रशासित है।
- उद्देश्य: कलात्मक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी कहने को प्रोत्साहित करना।
- श्रेणियों में फीचर फिल्में, गैर-फीचर फिल्में और सिनेमा पर लेखन शामिल हैं।

2. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार:

- 1969 में स्थापित, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान।
- भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान को मान्यता दी।

वर्तमान संदर्भ (71 वें पुरस्कार हाइलाइट्स)**• प्रमुख विजेता:**

- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार: मोहनलाल।
- बेस्ट मेल एक्टर: शाहरुख खान (जवान), विक्रान्त मैसी (12वीं फेल)।
- सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता: रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)
- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: 12वीं फेल।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशन: सुदीप्तो सेन (द केरल स्टोरी)।
- बेस्ट पॉपुलर फिल्म: राँकी और रानी की प्रेम कहानी।
- राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म: सैम बहादुर
- बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म: नाल 2.

• महिला-केंद्रित मान्यता:

- मूल्यों को आकार देने वाली माताओं को दर्शाने वाली फिल्मों को पुरस्कार, पितृसत्ता के खिलाफ एकजुट महिलाओं और साहसी महिला आवाजों को दर्शाने वाली फिल्में।
- सिनेमा में बच्चों और महिलाओं की भूमिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए लड़कियों सहित छह बाल कलाकारों को सम्मानित किया गया।

• राष्ट्रपति की टिप्पणी:

- जूरी पैनल में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आह्वान किया।
- सिनेमा से मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।
- लैंगिक न्याय और समानता के प्रति युवाओं की संवेदनशीलता को आकार देने में सिनेमा की भूमिका पर जोर दिया।

यूपीएससी मेन्स के लिए व्यापक विश्लेषण**1. सिनेमा और समाज:**

- सामाजिक वास्तविकताओं (पितृसत्ता, प्रवास, असमानता) को दर्शाता है।
- सामाजिक सुधार के एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है (उदाहरण के लिए, सीखने की अक्षमता पर तारे जमीन पर, महिलाओं की सहमति पर गुलाबी)।

2. महिलाओं का प्रतिनिधित्व:

- ऑन-स्क्रीन (नायक, कथा) और ऑफ-स्क्रीन (जूरी, निर्देशन, उत्पादन) दोनों अभी भी सीमित हैं।
- पुरस्कार जूरी पैनल में प्रतिनिधित्व समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

3. सॉफ्ट पावर और राष्ट्र-निर्माण:

- भारतीय सिनेमा विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में।
- पुरस्कार क्षेत्रीय फिल्मों और भाषाई विविधता (हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया, मराठी, आदि में विजेता) को प्रोत्साहित करते हैं।

निष्कर्ष

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केवल मनोरंजन से कहीं अधिक के रूप में सिनेमा की भूमिका की पुष्टि करते हैं - सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए एक सांस्कृतिक साधन। महिला केंद्रित फिल्मों और निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर राष्ट्रपति मुर्मू का जोर समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में सिनेमा की भूमिका को मजबूत करना, विशेष रूप से युवाओं के बीच, इसे भारत की समानता, न्याय और सांस्कृतिक जीवंतता की खोज में एक शक्तिशाली सहयोगी बना सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे 1954 में स्थापित किए गए थे और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रशासित हैं।
2. पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
3. दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान के रूप में की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

उत्तर: d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: लैंगिक समानता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने में भारतीय सिनेमा की भूमिका की जांच करें। आपके विचार में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसी राष्ट्रीय मान्यता इस भूमिका को कैसे मजबूत कर सकती है? (150 शब्द)

इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च (आईपीआर), गांधीनगर ने भारत के पहले फ्यूजन बिजली जनरेटर – एसएसटी-भारत के लिए एक रोडमैप जारी किया है, जिसका लक्ष्य 2060 तक चालू करना है। संलयन ऊर्जा, जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है, संभावित रूप से असीमित, स्वच्छ और कम अपशिष्ट ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है, लेकिन तकनीकी और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यह रोडमैप भारत को घरेलू ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को संतुलित करते हुए वैश्विक संलयन अनुसंधान में एकीकृत करने के लिए दीर्घकालिक पथ पर रखता है।

IPR Gandhinagar proposes roadmap for India's fusion power plans

Controlled fusion can only happen in extreme conditions, the kind that exists inside stars; there are currently two popular ways to achieve this: inertial confinement and magnetic confinement. India is already invested in the magnetic confinement technique as a member of the ITER project, which is building a reactor in France

Unnati Ashar

Researchers at the Institute for Plasma Research (IPR) in Gandhinagar have laid out a roadmap for India to achieve fusion power.

They envisage developing India's first fusion electricity generator, called the Steady-state Superconducting Tokamak Bharat (SST-Bharat), with a power output 5x the input. According to the team, it will be a fusion-fission hybrid reactor with 100 MW of the total 130 MW provided by fission. The estimated construction cost is ₹25,000 crore.

The team ultimately aims to commission a full-scale demonstration reactor by 2060 with an ambitious output-to-input power ratio of 20 and to generate 250 MW.

Fission to fusion

"Fusion is the process where two small, light atoms come together to form a bigger, heavier atom. When this happens, a huge amount of energy is released," Daniel Raju, Dean of academics and student affairs at IPR and lead author of the new study, said.

Nuclear fusion is the reason stars exist and produce heat and light.

For decades, fission reactors have provided the backbone for nuclear power. Fusion, however, is more attractive than fission because it produces less radioactive waste, eliminating many (but not all) of the costs and headaches of storing hazardous material.

Controlled fusion can only happen in extreme physical conditions, the kinds that exist in the belly of a star. There are currently two popular ways to achieve this: inertial confinement and magnetic confinement. Inertial confinement uses powerful lasers to blast a capsule with X-rays to initiate fusion. Magnetic confinement works by recreating some of the conditions inside stars.

India is already invested in magnetic confinement as a member of the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) project, which is building a large reactor in France. In this method, scientists heat plasma to 100 million degrees C, then gently guide the nuclei with magnetic fields until they fuse. To compare, temperatures in the sun's core reach 15 million degrees C.

Maintaining the plasma

The ratio of the output power to the input, called the Q value, determines efficiency.

"We need Q to be much greater than 1, meaning the reactor gives us more energy



This photograph shows bright plasma glowing inside the reactor vessel of the Mega Ampere Spherical Tokamak in Culham, UK. EYE STEEL FILM (CC BY)

than we use to run it. Right now, the best result has come from the Joint European Torus in the U.K., which got about 0.67, that is, 67% of the energy back," Raju said.

ITER aims to achieve a Q of 10. Future fusion power plants are expected to achieve a value of 20 to be commercially feasible. The doughnut-shaped reactor vessel in which fusion happens is called a tokamak. Its success is measured by how long it can hold the plasma together without dissipating.

"The longer we can hold it, the closer we get to continuous and reliable fusion reactions," Raju said.

In February 2025, the WEST tokamak in France maintained plasma for a record 22 minutes. The current state-of-the-art facility in India is the SST-1 tokamak at IPR. According to Raju, "It has managed to produce plasma for about 650 milliseconds, and it is designed to go up to 16 minutes."

SST-1 is a research machine and not meant to generate electricity. SST-Bharat is presented as the next step beyond this experimental base.

Digital twinning

To strengthen the new roadmap, the researchers have proposed digital twins – virtual replicas of physical systems that mimic real-time conditions inside a tokamak. This would allow scientists to test new designs and troubleshoot before building them physically. They also suggest machine learning-assisted plasma confinement and programmes to develop radiation-resistant materials. These

In February 2025, the WEST tokamak in France maintained plasma for a record 22 minutes

innovations are still at an early stage, but the roadmap argues they are critical to making progress.

Globally, however, timelines remain uncertain. The U.K.'s STEP programme aims for a prototype fusion plant by 2040. Several U.S. private firms claim they will demonstrate grid-connected fusion as early as the 2030s. China's EAST tokamak has already set records for plasma duration. India's target of 2060 places it on a longer path – one that may be less competitive but more cautious.

Funding and policy are crucial. While the EU and U.S. are investing billions of dollars in fusion R&D and private start-ups, India's budgets remain modest and almost entirely public-sector driven. The absence of Indian private-sector engagement stands out when compared with the global boom in fusion start-ups. Within India's wider energy policy, fusion also competes with pressing commitments: net zero by 2070, major expansions in solar and wind, and a long-standing nuclear fission programme.

Rough terrain

M.V. Ramana, Simons Chair in Disarmament, Global and Human Security at the University of British Columbia, also struck a note of caution on the prospects for fusion.

"Timelines in nuclear fusion are

realistic and often not achievable," Mr. Ramana emphasised.

He also pointed out that the economic viability of fusion power is unproven:

"The unstated assumption is that electrical power from this process will be affordable at some future date. There is no reason to expect that to be the case."

Raju himself acknowledged the cost challenge: "The economic viability of fusion energy will certainly face a huge challenge while competing with fission and other energy sources due to costs in R&D, construction, and operations."

Even if commercial viability remains elusive, the researchers argued that fusion R&D will produce dividends in other areas, including radiation-hardened materials, superconducting magnets, plasma modelling, and high-temperature engineering. These capabilities have strategic value, potentially upgrading Indian industry and strengthening technological autonomy. Partnerships with ITER and global firms may also spark innovation and bring project management expertise into Indian labs.

"Since its [commercial viability] hasn't been demonstrated so far, we are aware that it would be difficult to push it as a potential source of energy in the near future," Raju said. "Since a lot of private [entities], start-ups, and government bodies across the world are jumping into fusion energy, it makes sense for us to go with optimism and align our domestic fusion programmes with the world."

(Unnati Ashar is a freelance science journalist. unnati.a@gmail.com)

THE GIST

Fusion happens when two atoms fuse to form a bigger atom. A huge amount of energy is released as a result. Fusion reactors are more attractive than fission because they produce less radioactive waste, eliminating many costs associated with storing hazardous material

India participates in magnetic confinement research through the International Thermonuclear Experimental Reactor project in France. In this approach, scientists heat plasma to 100 million degrees Celsius and guide atomic nuclei to achieve fusion

Even if commercial viability remains elusive, researchers contend that fusion R&D will produce dividends in other areas, including radiation-hardened materials, superconducting magnets, plasma modelling, and high-temperature engineering

स्थैतिक संदर्भ

1. परमाणु विखंडन बनाम संलयन

- विखंडन: भारी नाभिक (यूरेनियम, प्लूटोनियम) का विभाजन; 1950 के दशक से व्यावसायिक उपयोग।
- संलयन: प्रकाश नाभिक (हाइड्रोजन समस्थानिक) को हीलियम में मिलाना, बड़े पैमाने पर ऊर्जा (सितारों का आधार) जारी करना।

2. फ्यूजन आकर्षक क्यों है?

- विखंडन की तुलना में कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट पैदा करता है।
- प्रचुर मात्रा में ईंधन (समुद्री जल से ड्यूटेरियम, ट्रिटियम प्रजनन के लिए लिथियम)।
- स्वाभाविक रूप से सुरक्षित (चेरनोबिल की तरह कोई भगोड़ा प्रतिक्रिया नहीं)।

3. कारावास तकनीक

- चुंबकीय कारावास: टोकामक्स; प्लाज्मा ~ 100 मिलियन °C तक गर्म होता है, चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से निहित।
- जड़त्वीय कारावास: लेजर संलयन को ट्रिगर करने के लिए ईंधन गोली को संपीड़ित करते हैं।

4. भारत का वर्तमान संलयन कार्य

- आईटीईआर (इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, फ्रांस) के सदस्य - दुनिया की सबसे बड़ी टोकामक परियोजना, जिसका लक्ष्य $Q=10$ है।
- घरेलू मशीन: एसएसटी-1 टोकामक (आईपीआर गांधीनगर) - अनुसंधान-केंद्रित, बिजली उत्पादन नहीं।

वर्तमान संदर्भ

• SST-भारत प्रस्ताव:

- हाइब्रिड रिएक्टर: विखंडन से 100 मेगावाट + संलयन से 30 मेगावाट (प्रथम चरण)।
- लागत अनुमान: ₹25,000 करोड़।
- दीर्घकालिक लक्ष्य: 2060 तक 250 मेगावाट पूर्ण पैमाने पर रिएक्टर $Q=20$ (व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य) के साथ।

• प्रस्तावित तकनीकी नवाचार:

- डिजिटल जुड़वां: परीक्षण और समस्या निवारण के लिए वर्चुअल रिएक्टर मॉडल।
- मशीन लर्निंग: प्लाज्मा कारावास अनुकूलन।
- विकिरण प्रतिरोधी सामग्री और सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट।

• वैश्विक परिदृश्य:

- यूके स्टेप कार्यक्रम: 2040 तक प्रोटोटाइप।
- अमेरिकी निजी फर्म: 2030 के दशक तक ग्रिड से जुड़े संलयन का वादा करती हैं।
- चीन का पूर्वी टोकामक: विश्व रिकॉर्ड प्लाज्मा अवधि।
- भारत की समयरेखा (2060) = अधिक सतर्क, कम प्रतिस्पर्धी।

• चुनौतियों:

- अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रायोगिक क्यू: 0.67 (संयुक्त यूरोपीय टोरस, यूके)।
- आईटीईआर क्यू = 10 के लिए उम्मीद करता है; वाणिज्यिक संयंत्रों को $Q \approx 20$ की आवश्यकता होती है।
- भारत का वित्त पोषण मामूली है, लगभग पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र; बहुत कम निजी भागीदारी।

- भारत के 2070 नेट-जीरो मार्ग में सौर, पवन और विखंडन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- पेशेवरों:

- उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता।
- स्पिन-ऑफ: सुपरकंडक्टर्स, विकिरण-कठोर सामग्री, एआई-संचालित मॉडलिंग।
- भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

- विपक्ष:

- वाणिज्यिक व्यवहार्यता अनिश्चित; लागत बहुत अधिक है।
- लंबे समय तक (लक्ष्य 2060) अप्रासंगिकता का जोखिम है यदि सौर + भंडारण पहले हावी हो जाता है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव = नवाचार का अंतर।

निष्कर्ष

भारत का फ्यूजन रोडमैप आकांक्षात्मक और सतर्क है, जो आशावाद और यथार्थवाद दोनों को दर्शाता है। हालांकि वाणिज्यिक व्यवहार्यता अनिश्चित बनी हुई है, सामग्री विज्ञान से लेकर प्लाज्मा भौतिकी तक अनुसंधान एवं विकास लाभांश भारत के तकनीकी आधार को उन्नत कर सकता है। अभी के लिए, फ्यूजन एक निकट अवधि का ऊर्जा समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन निरंतर निवेश यह सुनिश्चित करता है कि भारत भविष्य की सफलता में पीछे न रहे। वैश्विक सहयोग, निजी निवेश और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के साथ फ्यूजन अनुसंधान एवं विकास को संरक्षित करना इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : नाभिकीय संलयन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संलयन विखंडन की तुलना में कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट पैदा करता है।
2. चुंबकीय कारावास संलयन के लिए सूर्य के मूल की तुलना में अधिक प्लाज्मा तापमान की आवश्यकता होती है।
3. भारत फ्रांस में आईटीईआर परियोजना का सदस्य है, जो जड़त्वीय कारावास पर आधारित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: क)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: प्रस्तावित एसएसटी-भारत परियोजना सहित परमाणु संलयन के लिए भारत का रोडमैप, वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और आर्थिक सावधानी दोनों को दर्शाता है। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत के संलयन अनुसंधान कार्यक्रम के संभावित लाभों, चुनौतियों और रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। (150 शब्द)

भारत-चीन सीमा ऐतिहासिक बहस का विषय रही है, दोनों पक्ष विरासत के नक्शे, ऐतिहासिक नियंत्रण और रणनीतिक विचारों के आधार पर दावों पर जोर देते हैं। जबकि 1914 के शिमला सम्मेलन और मांचू-युग के नक्शे स्पष्ट ऐतिहासिक सीमाओं का संकेत देते हैं, बाद में चीन गणराज्य (आरओसी) और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के दावों ने स्थिति को जटिल बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन में समकालीन सीमा विवादों की सराहना करने के लिए इन सीमाओं की उत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है।

The mapping of the India-China border

During the Simla Conference, the delegate from the Republic of China categorically maintained that Tibet had no claim to the territories of the tribal belt (corresponding to present day Arunachal Pradesh) on the Assam side of the Himalayan divide, for they were not ethnically Tibetan and were self-governing

WORLD INSIGHT

Sunil Khatri

In a three-part series on the India-China border issue that appeared in the columns of *The Hindu* from September 5-9, 2025, the author, Manoj Joshi, develops a narrative on the assertion that the India-China border was not properly defined. This article presents another view on the same.

Official Manchu maps

During the 267-year Manchu rule (1644-1911), two major maps of the Empire, drawn to scale with coordinate lines, were prepared with the assistance of European Jesuits. The first is Emperor Kang-hsi's map (1721), depicting the territorial bequest of the Tibet-Assam segment to the then Republic of China (RoC). In the map, Tibet was never conceived as a trans-Himalayan state. Its southern boundary extended only upto the Himalayas, for Tibetans never resided on the southern side of the Himalayan divide. Consequently, non-Tibetan Tawang, south of the Himalayan divide, although Buddhist, was not depicted as Tibetan territory. Corroborative evidence in this regard comes from the RoC delegate's statement during the Simla Conference (1913-14), in which he categorically maintained that Tibet had no claim to the territories of the tribal belt (corresponding to present day Arunachal Pradesh) on the Assam side of the Himalayan divide, for they were not ethnically Tibetan and were self-governing.

Moreover, the RoC delegate did not claim this non-Tibetan tribal-belt on behalf of his country, leaving it to the Indian delegate to include it in Assam as it had already been under its sphere of influence for centuries. The resultant Indo-Tibetan boundary agreement in March 1914, also called the 1914 alignment, was in keeping with Kang-hsi's



Clear boundaries: Indian Army and ITBP personnel, along with villagers and students, participate in a 'Tiranga Rally' at the forward areas of China in Tawang district, Arunachal Pradesh on August 14, 2011

map.

The second Manchu map that depicts its territorial bequest to the RoC in the eastern Turkestan-Kashmir segment is Emperor Ch'ien-lung's map (1761), which shows that Eastern Turkestan (a region in the northwestern part of the now People's Republic of China) was never conceived as a trans-Kunlun territory (mountain range abutting eastern Turkistan). Consequently, the Manchu never claimed the stretch of desolate area south of the Kunlun mountain extending all the way upto the Hindu Kush-Karakoram mountains, lying further south. A proposal was submitted to the Manchu Foreign Office in 1899 suggesting the division of this area on the watershed principle, resulting in the Kashmir-Sinkiang boundary line, which became the 1899 alignment (related to the Aksai Chin region).

Territorial claims to the contrary

Apart from the official Manchu maps cited above, there is no subsequent official Manchu map. In 1943, when World War II was at its peak, a tottering RoC felt emboldened enough to set aside the Manchu's territorial bequest (1721 & 1761 maps), resulting in the emergence of a claim to large tracts of Indian territory. On being questioned on the new map, the RoC's response was, "The map was but an unprecise draft, to be corrected later on." A similar map was repeated by the RoC in December 1947, at a vulnerable moment, when a newly independent India's energies were directed on its military conflict with Pakistan.

China retained the same map-making pattern set by its predecessor regime. In a rare moment of candour in Peking in October 1954, Chou En-lai, the then Chinese Premier acknowledged in the

presence of the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, "...it is a historical question and we have been mostly printing old maps...At least we do not have any deliberate intentions of changing boundaries as KMT (RoC) had. The whole thing is ridiculous....".

It has been shown that during his talks with Jawaharlal Nehru on the boundary question in New Delhi in April 1960, Chou En-lai had, more or less, conjured up a narrative in support of the Chinese position. He did so by attempting to pick holes in the evidence in support of India's claim through a clever play of words and assertions, not backed by facts. However, he was cautious in making a reference to evidence of Chinese origin, for he knew that here he could be skating on thin ice.

He slowly revealed his tactic to resolve the boundary question: that instead of focusing on maps and documents alone, both sides should agree to the use of a set of principles, enunciated by him, for a resolution. This was a trap, as reasoned by former Foreign Secretary Vijay Gokhale in his book, *The Long Game*.

There appears to be no evidence in the public domain to suggest that Chou En-lai had proposed a territorial swap – where India would concede to the Chinese position in the Aksai Chin region in exchange for Chinese acceptance of India's claim over Arunachal Pradesh.

Instead, the way forward, as agreed to by both parties, was through a package deal that would aim at resolving not only the entire length of the boundary, but also address other pending geopolitical and trade-related matters. To break the impasse, both sides would need to work towards a "...solution which brings no defeat to any side and that it should be reasonable, equitable and friendly...and which is...consistent with dignity and self-respect of both countries." The broad contours of such a solution could possibly lead to the acceptance of the 1899 and 1914 alignments respectively, with a provision for a territorial swap to meet each other's security concerns.

The author is a former civil servant.

THE GIST

During the 267-year Manchu rule, two major maps of the Empire were prepared. The first is Emperor Kang-hsi's map (1721), depicting the territorial bequest of the Tibet-Assam segment to the then Republic of China (RoC).

The second Manchu map that depicts its territorial bequest to the RoC in the eastern Turkestan-Kashmir segment is Emperor Ch'ien-lung's map (1761).

In 1943, when World War II was at its peak, a tottering RoC felt emboldened enough to set aside the Manchu's territorial bequest.

स्थैतिक संदर्भ

1. ऐतिहासिक मानचित्र और समझौते:

○ मांचू मानचित्र (1644-1911):

- कांग-हिस (1721): हिमालय तक तिब्बत की दक्षिणी सीमा; तवांग (विभाजन के दक्षिण) तिब्बती नहीं।
- चिएन-लुंग (1761): पूर्वी तुर्किस्तान-कश्मीर खंड; कुनलुन रेंज के दक्षिण में हिंदू कुश-काराकोरम पहाड़ों तक कोई दावा नहीं है।

- 1914 शिमला सम्मेलन: आरओसी प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि असम आदिवासी बेल्ट (वर्तमान अरुणाचल प्रदेश) पर तिब्बत का कोई दावा नहीं है।
- 1899 संरेखण: वाटरशेड सिद्धांत पर आधारित प्रस्तावित कश्मीर-सिंकियांग सीमा।

2. सीमाओं के लिए मुख्य सिद्धांत:

- जातीय संरचना और स्थानीय आबादी का स्वशासन।
- ऐतिहासिक प्रशासनिक नियंत्रण।
- वाटरशेड और स्थलाकृतिक विचार।

वर्तमान संदर्भ

1. चीनी दावों में बदलाव:

- 1943 के बाद, ROC ने ऐतिहासिक मांचू मानचित्रों की अनदेखी करते हुए भारतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से का दावा करने वाले नक्शे तैयार किए।
- 1947: भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बीच इसी तरह के नक्शे जारी किए गए।
- पीआरसी को यह मानचित्र परंपरा विरासत में मिली, कभी-कभी सीमाओं को बदलने के इरादे के बिना पुराने मानचित्रों को छापने की बात स्वीकार की जाती है (चाउ एन-लाई, 1954)।

2. राजनयिक युद्धाभ्यास:

- चाउ एन-लाई (नेहरू के साथ 1960 की वार्ता) ने चीनी मूल के सबूतों पर निर्भरता से परहेज किया, इसके बजाय बातचीत के समाधान के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया।
- न्यायसंगत, गरिमापूर्ण और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधानों पर जोर, संभवतः इसमें शामिल हैं:
 - 1899 (अक्साई चिन) और 1914 (अरुणाचल प्रदेश) संरेखण की स्वीकृति।
 - सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए क्षेत्रीय अदला-बदली का प्रावधान।

3. वर्तमान स्थिति:

- भारत अरुणाचल प्रदेश पर ऐतिहासिक दावा रखता है, जो मानचित्रों और औपनिवेशिक युग के समझौतों द्वारा समर्थित है।
- अक्साई चिन चीनी नियंत्रण में है, जो व्यापक अनसुलझे सीमा मुद्दे का हिस्सा है।
- सीमा विवाद हिमालय में भू-राजनीति, व्यापार और सैन्य तैनाती को प्रभावित करना जारी रखते हैं।

निष्कर्ष

मांचू मानचित्र और शिमला सम्मेलन की कार्यवाही सहित ऐतिहासिक साक्ष्य अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे का समर्थन करते हैं, जबकि 1899 और 1914 के संरेखण संभावित बातचीत के समाधान के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, आरओसी और पीआरसी द्वारा स्वतंत्रता के बाद के दावे परिदृश्य को जटिल बनाते हैं। आगे बढ़ते हुए, एक सैद्धांतिक, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक दृष्टिकोण - संभवतः क्षेत्रीय अदला-बदली और सुरक्षा आश्वासन को शामिल करते हुए - क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखते हुए भारत-चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए सबसे व्यवहार्य मार्ग बना हुआ है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: मांचू-युग के मानचित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. कांग-हर के 1721 के नक्शे में हिमालय तक तिब्बत की दक्षिणी सीमा को दर्शाया गया था।
2. चिएन-लुंग के 1761 के नक्शे में अक्साई चिन को कुनलुन पर्वत के दक्षिण में तिब्बत के हिस्से के रूप में दिखाया गया था।
3. तवांग (अरुणाचल प्रदेश) को तिब्बती क्षेत्र नहीं माना जाता था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- C) केवल 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत-चीन सीमा विवाद के ऐतिहासिक आधार और समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करें। एक न्यायसंगत समाधान के लिए आगे के रास्ते सुझाएं। **(150 शब्द)**

Page : 08 Editorial Analysis

Right to state

Recognition of Palestine is more than just symbolic

When the state of Israel was declared in Palestine on May 14, 1948, the U.S. recognised it in just 11 minutes. In the years since, most UN members extended recognition to the Jewish nation, which became a UN member in 1949. When the Palestine Liberation Organisation (PLO) declared a state of Palestine in 1988, much of the Global South recognised it, but powerful western nations stayed away with the position that recognition would come only as part of a negotiated two-state settlement. But this week, at the UN General Assembly, the U.K., France, Canada and Australia finally recognised Palestine, which shows their fraying ties with Israel and diminishing faith in a coercion-free diplomatic process leading to a final settlement. For Palestinians, the western recognition could be seen as a diplomatic respite but comes too late – Gaza has been devastated by Israeli forces; Jewish settlements and Israeli checkpoints have mushroomed in the West Bank; and settler violence has displaced thousands of Palestinians over the past two years. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu openly declares that there will never be a Palestinian state, and Washington offers Israel unconditional support.

Recognition may not have an immediate impact on the ground. Israel's ruling coalition is incapable of even ending the slaughter in Gaza, let alone discuss a two-state solution. Yet, this wave of recognition is not just a symbolic act. It shows cracks in the post-1948 pro-Israel consensus in the West. The U.K. played a decisive role in the establishment of the state of Israel. France armed it in its early years and helped it build nuclear weapons. These powers bear historical responsibility to find a solution to the problem they were a party to from the beginning. And Palestinians have an internationally recognised right to have their own independent, sovereign state. If Israel does not stop the war in Gaza, which should be the first step, and continues with the settlements in the West Bank, Europe should impose an arms embargo on Tel Aviv. Israel should be warned against annexing the West Bank, which should be treated as a red line. Mr. Netanyahu and his extremist Ministers, though internationally isolated, will not be persuaded. But they will not rule forever. A future Israeli leader could abandon Mr. Netanyahu's militarism. This forever war and genocidal tag are not helping Israel's interests either, even though it allows Mr. Netanyahu to cling on to power. The recognition of today should serve as a stepping stone for a Palestinian state tomorrow. That is the best chance for peace for Palestinians, Israelis and West Asia.

GS. Paper 02- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: फिलिस्तीन की हाल ही में पश्चिमी मान्यता की जांच करें और पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति के लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण करें। (150 शब्द)

संदर्भ:

यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी, जो पश्चिमी राजनयिक स्थिति में एक ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित करता है। हालांकि मान्यता जमीनी वास्तविकताओं को तुरंत नहीं बदल सकती है, यह 1948 के बाद की इजरायल समर्थक आम सहमति में दरारों को दर्शाती है और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की आधारशिला को रेखांकित करती है।

स्थैतिक संदर्भ

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 1948 : इजराइल ने अमेरिका और बाद में संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों द्वारा तेजी से मान्यता प्राप्त करने की घोषणा की।
- 1988 : फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) ने फिलिस्तीन राज्य घोषित किया; कई वैश्विक दक्षिण देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- पश्चिमी रुख: मान्यता को रोक दिया गया, यह तर्क देते हुए कि एक फिलिस्तीनी राज्य को बातचीत के दो-राज्य समाधान के माध्यम से उभरना चाहिए।

2. अंतराष्ट्रीय कानून का आधार:

- आत्मनिर्णय का अधिकार: संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अनुच्छेद 1 और 55) और आईसीसीपीआर/आईसीईएससीआर में निहित है।
- मान्यता एक राजनीतिक कार्य है लेकिन कानूनी और राजनयिक वैधता प्रदान करती है।

वर्तमान संदर्भ

1. पश्चिमी मान्यता:

- ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को स्वीकार किया, संकेत दिया:
 - बिना शर्त इजरायल समर्थक सहमति का क्षरण।
 - गतिरोध वाली शांति वार्ता से बढ़ती निराशा।
 - गाजा और वेस्ट बैंक बस्तियों में इजरायली नीतियों की अप्रत्यक्ष आलोचना।

2. जमीनी वास्तविकताएँ:

- गाजा संघर्ष से तबाह बना हुआ है।
- वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों और चौकियों का विस्तार होता है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य का दर्जा तुरंत संप्रभुता या क्षेत्र नियंत्रण में तब्दील नहीं होता है।

3. राजनयिक निहितार्थ:

- यदि इजराइल वेस्ट बैंक की लाल रेखाओं का उल्लंघन करता है तो हथियार प्रतिबंध या प्रतिबंधों की संभावना।
- मान्यता बहुपक्षीय मंचों में फिलिस्तीनी दावों को मजबूत करती है।
- भविष्य के इजरायली नेतृत्व पर सैन्यवादी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव डाल सकते हैं।

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- पेशेवरों:
 - फिलिस्तीन को राजनयिक वैधता प्रदान करता है।
 - इजराइल के लिए पूर्ण पश्चिमी समर्थन के कमजोर होने का संकेत, बातचीत के रास्ते खोलना।
 - पश्चिमी शक्तियों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया जाता है।
- विपक्ष/सीमाएँ:
 - गाजा या वेस्ट बैंक में जमीन पर कोई तत्काल राहत नहीं।
 - इजरायली राजनीतिक नेतृत्व (नेतन्याहू) द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की संभावना नहीं है।
 - मान्यता प्रतीकात्मक है जब तक कि लागू करने योग्य उपायों (हथियार प्रतिबंध, प्रतिबंध) द्वारा समर्थित न हो।

निष्कर्ष

प्रमुख पश्चिमी शक्तियों द्वारा फिलिस्तीन की मान्यता प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है - यह अंतरराष्ट्रीय वैधता की दिशा में एक कदम है और भविष्य के दो-राज्य समाधान के लिए एक संभावित आधार है। जबकि जड़ें जमा चुके संघर्ष के कारण तत्काल प्रभाव सीमित हो सकता है, ऐतिहासिक जवाबदेही, अंतराष्ट्रीय कानून और वैश्विक राजनयिक दबाव शांतिपूर्ण समाधान के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे फिलिस्तीनियों, इजरायलियों और व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र को लाभ होता है।